

क्षेत्र, चंडीगढ़. (टुली, जे.)

बिक्री कर मामला

हरबंस सिंह, सी.जे. और बाल राज तुली से पहले, जे.

मेसर्स चरणजीत लाल-देस राज-याचिकाकर्ता।

बनाम

बिक्री कर न्यायाधिकरण, संघ राज्य क्षेत्र।

चंडीगढ़,-प्रतिवादी।

1972 का सेल्स टैक्स केस नंबर 3
23 अप्रैल 1973.

पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट (1948 का एक्सएलवीआई) - धारा 22(1) - इसमें इस्तेमाल किया गया शब्द "कर" - इसमें "जुर्माना" शामिल है - जुर्माना लगाने का आदेश - इससे उत्पन्न होने वाले कानून का प्रश्न - क्या इसे उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है धारा 22(1) के तहत.

माना गया कि "जुर्माना" का बिक्री कर से सीधा संबंध है, जिसके लिए एक डीलर का मूल्यांकन किया जाता है। जुर्माने की मात्रा का संबंध निर्धारित या चोरी किये गये कर से भी होता है। जुर्माना लगने के बाद यह अतिरिक्त कर का रूप ले लेता है, जो डीलर से उसी प्रकार वसूल किया जाता है, जिस प्रकार कर निर्धारण किया गया है। इसलिए पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1948 की धारा 22(1) में प्रयुक्त शब्द "टैक्स" में निर्धारित कर और लगाया गया जुर्माना दोनों शामिल हैं और सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल के जुर्माना लगाने के आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्न पर एक संदर्भ भी शामिल है। उस धारा के तहत उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। (पैरा 2 और 5).

पंजाब जनरल की धारा 22(2)(बी) और (3) के तहत याचिका बिक्री कर अधिनियम, 1948, प्रार्थना करते हुए कि बिक्री कर न्यायाधिकरण, संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ को यह बताने और मामले को यहां भेजने का निर्देश दिया जाए

क्षेत्र, चंडीगढ़. (टुली, जे.)

कानून के निम्नलिखित प्रश्नों पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय हेतु अपील क्रमांक 20/1971 में दिनांक 22 फरवरी 1972 के उनके निर्णय से।

(i) क्या यू.टी., चंडीगढ़ का एक पंजीकृत डीलर, जो हरियाणा राज्य के एक पंजीकृत डीलर से बिक्री के लिए कुछ सामान खरीदता है, हरियाणा राज्य द्वारा निर्धारित उक्त हरियाना पंजीकृत डीलर को फॉर्म नंबर 'ई' में घोषणा जारी करने के बाद सरकार, - अपनी अधिसूचना संख्या एस.ओ. द्वारा। 41/सी.ए. 74/56/एस-8/67, दिनांक 2 मई, 1967. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 या उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के नियमों के तहत कोई अपराध करता है, जब वह उक्त माल को बिक्री के लिए स्थानांतरित करता है कुछ कारणों से, पंजाब राज्य या भारत संघ के किसी अन्य राज्य में उसके शाखा कार्यालय या प्रधान कार्यालय को:

(ii) क्या उपर्युक्त हरियाणा राज्य सरकार की अधिसूचना में चंडीगढ़ (यू.टी.) के क्रय डीलर द्वारा उक्त अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन के लिए कोई जुर्माना निर्धारित किया गया है:

(iii) क्या उपरोक्त हरियाणा राज्य सरकार की अधिसूचना की शर्तों का उल्लंघन, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10 (डी) के तहत आता है, जिसके लिए यू.टी., चंडीगढ़ के क्रय डीलरों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।, उक्त अधिनियम की धारा 10-ए के तहत;

(iv) क्या निर्धारण प्राधिकारी (बिक्री कर), यू.टी. चंडीगढ़ के पास यू.टी., चंडीगढ़ के एक पंजीकृत डीलर पर उक्त अधिनियम की धारा 10-ए के तहत कोई जुर्माना लगाने का अधिकार क्षेत्र है, जिसने हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना की शर्तों का उल्लंघन किया है;

(v) जहां तक यू.टी., चंडीगढ़ का संबंध है, क्या आवेदक उक्त सामान का डीलर है, जो कि वह है। हरियाणा राज्य के एक पंजीकृत डीलर से 'ई' फॉर्म पर खरीदा गया, और उसी सामान को यू.टी., चंडीगढ़ से बाहर किसी राज्य में अपने शाखा कार्यालय या प्रधान कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया;

(vi) क्या उक्त अधिसूचना में 'उपभोग या उपयोग' शब्द में एक पंजीकृत डीलर द्वारा यू.टी., चंडीगढ़ के बाहर किसी राज्य में उसके मुख्य कार्यालय या शाखा कार्यालय में बिक्री के लिए माल का हस्तांतरण शामिल है;

(vii) जब आवेदक ने कुछ कारणों से उक्त सामान को यू.टी., चंडीगढ़ से बाहर अपने मुख्य कार्यालय या शाखा कार्यालय में बिक्री के लिए स्थानांतरित किया; क्या यह माना जा सकता है कि उसने उक्त सामान को उस उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए रखा था जिसके लिए उसने खरीद के समय उक्त सामान का इरादा किया था;

(viii) क्या हरियाणा राज्य सरकार के पास केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(5) के तहत बिक्री की खरीद या शाखा कार्यालय से मुख्य कार्यालय या शाखा कार्यालय से दूसरे शाखा कार्यालय में माल के हस्तांतरण के लिए कोई शर्त लगाने की कोई शक्ति है। अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विभिन्न राज्यों में शाखा कार्यालय;

क्षेत्र, चंडीगढ़. (टुली, जे.)

(ix) क्या उपर्युक्त हरियाणा राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्धारित 'ई' फॉर्म, केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और टर्नओवर) के तहत विभिन्न राज्यों के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा कर मुक्त खरीद करने के लिए 'सी' फॉर्म का विकल्प है। नियम, 1957. यदि 'ई' फॉर्म 'सी' फॉर्म का विकल्प है, तो क्या 'सी' फॉर्म के आधार पर खरीदा गया सामान किसी अन्य शाखा कार्यालय या प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा कार्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है; विभिन्न राज्यों में स्थित है। यदि वे स्थानांतरण कर सकते हैं, तो क्या माल के ऐसे हस्तांतरण के लिए उन पर धारा 10-ए के साथ पठित धारा 10(डी) के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है;

(x) क्या यू.टी. चंडीगढ़ में शाखा कार्यालय अपने मुख्य कार्यालय या दूसरे राज्य में शाखा कार्यालय को कुछ सामान बेच सकता है। क्या ऐसा लेन-देन व्यापार और वाणिज्य के सामान्य क्रम में बिक्री के बराबर हो सकता है।

(xi) क्या बिक्री कर न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया आवेदन इस बात में अक्षम था कि क्या अभिव्यक्ति "कर" में जुर्माना शामिल है।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील आर.एन. नरूला।

प्रतिवादियों की ओर से आनंद सरूप, अधिवक्ता, एम. एल. पुरी, अधिवक्ता के साथ।

निर्णय
न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:-

टुली, जे.-याचिकाकर्ता मिट्टी के तेल और स्नेहक का कारोबार करने वाली एक कंपनी है। यह पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (इसके बाद पंजाब अधिनियम कहा जाएगा) और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत एक डीलर के रूप में पंजीकृत है। वर्ष 1967-68 के लिए, मूल्यांकन प्राधिकारी ने पंजाब अधिनियम और केंद्रीय अधिनियम दोनों के तहत, 20 जुलाई, 1971 के आदेश द्वारा मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा यह माना गया कि याचिकाकर्ता-फर्म ने अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र का दुरुपयोग किया था, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में उपभोग और उपयोग के लिए 'ई' फॉर्म जारी करने के बाद हरियाणा के पंजीकृत डीलरों से सामान खरीदा गया था, लेकिन इसके बजाय, माल पंजाब राज्य में खन्ना और दोराहा में इसकी शाखाओं में भेजा गया और रुपये का जुर्माना लगाया गया। 7,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। उस आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त के समक्ष अपील दायर की, जिसे 23 अक्टूबर, 1971 को खारिज कर दिया गया। बिक्री कर न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ में आगे की अपील भी 22 फरवरी, 1972 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई। ट्रिब्यूनल के आदेश से उत्पन्न होने वाले कथित कानून के दस प्रश्नों को संदर्भित करने के लिए

मेसर्स चरणजीत लाल, देस राज बनाम सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल,

क्षेत्र, चंडीगढ़. (टुली, जे.)

पंजाब अधिनियम की धारा 22(1) के तहत एक आवेदन किया। उस आवेदन को सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल ने 27 जून 1972 को इस आधार पर

खारिज कर दिया था कि धारा 22 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कर" में जुर्माना शामिल नहीं था और इसलिए आवेदन सक्षम नहीं था। व्यथित महसूस करते हुए याचिकाकर्ता ने पंजाब अधिनियम की धारा 22(2)(बी) और (3) के तहत बिक्री कर न्यायाधिकरण को मामले को बताने और संदर्भित करने का निर्देश देने के लिए वर्तमान याचिका दायर की है। निर्णय के लिए इस न्यायालय में आवेदन में उल्लिखित कानून के प्रश्न।

(2) अधिनियम की धारा 22(1) इस प्रकार है: -

“ट्रिब्यूनल द्वारा धारा 20 या 21 के तहत एक आदेश पारित होने से 60 दिनों के भीतर, इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए किसी भी डीलर के किसी भी दायित्व को प्रभावित करते हुए, ऐसे डीलर या आयुक्त, शुल्क या एक सौ रुपये के साथ लिखित रूप में आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन किसी डीलर द्वारा किया जाता है, तो ट्रिब्यूनल को ऐसे पुराने से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न को उच्च न्यायालय में संदर्भित करने की आवश्यकता होती है। इस मामले में निर्धारण के लिए प्रश्न यह है कि क्या इस उपधारा में प्रयुक्त शब्द "कर" में जुर्माना शामिल है। यदि निर्धारिती निम्नलिखित में से कोई भी चूक करता है तो इस अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाता है: -

(1) निर्धारित समय के भीतर टर्नओवर का रिटर्न दाखिल न करना।

(2) रिटर्न दाखिल करने या अन्यथा अग्रिम कर जमा न करना।

(3) मूल्यांकन के बाद कर का भुगतान न करना।

(4) पंजीकरण प्रमाणपत्र का दुरुपयोग।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जुर्माने का बिक्री कर से सीधा संबंध है, जिस पर डीलर का मूल्यांकन किया जाता है और जुर्माने की मात्रा का मूल्यांकन या चोरी किए गए कर से भी संबंध है। जुर्माना लगाए जाने के बाद, यह अतिरिक्त कर का रूप ले लेता है जो डीलर से उसी तरह वसूला जाता है जिस तरह से कर का निर्धारण किया जाता है। सी. ए. अब्राहम बनाम आयकर अधिकारी, कोट्टायम और अन्य (1) में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए प्रश्न यह था कि क्या आयकर अधिनियम, 1922 के अध्याय IV के प्रावधान, दंड के मूल्यांकन पर लागू थे जो कि था उक्त अधिनियम की धारा 28 के तहत अधिरोपणीय। ये हुआ था: -

क्षेत्र, चंडीगढ़. (टुली, जे.)

"इन धाराओं में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "मूल्यांकन" का उपयोग केवल आय की गणना के अर्थ में नहीं किया जाता है और हमारे निर्णय में यह मानने का कोई आधार नहीं है कि जब धारा 44 द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि एसोसिएशन के भागीदार या सदस्य होंगे मूल्यांकन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी, इसका उद्देश्य केवल धारा 23 के तहत आय की गणना के लिए दायित्व की घोषणा करना है, न कि कर दायित्व की घोषणा और लागू करने की प्रक्रिया और उसके प्रवर्तन के लिए मशीनरी को लागू करना। न ही अभिव्यक्ति 'अध्याय IV के सभी प्रावधान अब तक ऐसे मूल्यांकन पर लागू होंगे' एक प्रतिबंधित सामग्री है: शब्दों में यह कहता है कि अध्याय IV के सभी प्रावधान उस फर्म के मूल्यांकन पर लागू होंगे जो बंद हो गया है उनका व्यवसाय। धारा 28 के अनुसार अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायित्व निर्धारिती के बेईमान या अपमानजनक आचरण के मद्देनजर लगाया गया जुर्माना है।

बाद के मामले में, आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश बनाम मैसर्स। भीकाजी दादाभाई एंड कंपनी (2), सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने अब्राहम के मामले (सुप्रा) में उपरोक्त टिप्पणियों का उल्लेख किया और निम्नानुसार कहा: -

"इस अदालत ने जुर्माने को किसी व्यक्ति पर उसके बेईमान या अपमानजनक आचरण के मद्देनजर लगाया गया अतिरिक्त कर माना। यह सच है कि हैदराबाद आयकर अधिनियम के तहत, देय कर और जुर्माने की वसूली के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं, लेकिन हमारे फैसले में यह दोनों अधिनियमों के तहत लगाए गए जुर्माने के वास्तविक चरित्र को नहीं बदलता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जुर्माना एक अतिरिक्त कर है जिसे मूल कर के समान ही लगाया और वसूला जाता है।

(3) गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले पर विश्वा एंड कंपनी बनाम गुजरात राज्य (3) में विचार किया और बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1953 की धारा 34(1) की व्याख्या पर विचार किया, कि इससे संबंधित एक प्रश्न उक्त अधिनियम की धारा 16(4) के तहत जुर्माना लगाने का मामला धारा 34(1) के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा उच्च न्यायालय को भेजा जा सकता है। बॉम्बे एक्ट की धारा 34(1) पंजाब एक्ट की धारा 22(1) के समान है, और इसलिए, यह निर्णय सीधे तौर पर प्रासंगिक है।

क्षेत्र, चंडीगढ़. (टुली, जे.)

(4) हालांकि, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि जुर्माना "कर" शब्द में शामिल नहीं है और इसलिए, जुर्माना लगाने के आदेश से उत्पन्न होने वाला कोई भी संदर्भ धारा 22 के तहत इस न्यायालय में नहीं दिया जा सकता है। कार्यवाही करना। मया राम भाटिया बनाम उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (4) में इस न्यायालय की एकल पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह कहा गया था-

"इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 1964 में, जब याचिकाकर्ता ने अपील दायर की, तो अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के तहत अपील पर विचार करने से पहले जुर्माना की राशि का भुगतान करना आवश्यक नहीं था।"

उस मामले में मूल्यांकन का अंतिम आदेश 20 फरवरी को किया गया था। 1964 और रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश। निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, 15 सितंबर, 1964 को 25,000 रुपये की राशि एकपक्षीय रूप से पारित कर दी गई। उस आदेश के खिलाफ निर्धारिती ने उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने 18 फरवरी, 1965 को इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि निर्धारिती पर लगाए गए जुर्माने की राशि अपील दायर करने से पहले जमा नहीं की गई थी। धारा 20 का प्रावधान, जैसा कि उस समय लागू था, इस प्रकार था: -

"बशर्ते कि ऐसे प्राधिकारी द्वारा किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा- जब तक वह संतुष्ट न हो जाए कि निर्धारित कर की राशि और डीलर पर लगाया गया जुर्माना, यदि कोई हो, का भुगतान कर दिया गया है।"

उस प्रावधान को बाद में इस प्रकार संशोधित किया गया: - "अपील प्राधिकारी द्वारा किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अपील के साथ कर के भुगतान या लगाए गए जुर्माने, यदि कोई हो, या दोनों का संतोषजनक सबूत न हो। मामला हो सकता है।"

अलग-अलग समय पर धारा 20 के प्रावधान की भाषा की तुलना करके यह माना गया कि 1964 में अपील दायर करने से पहले निर्धारिती जुर्माने की राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। यह निर्णय स्पष्ट रूप से पंजाब अधिनियम की धारा 22(1) में "कर" शब्द की व्याख्या करने में किसी काम का नहीं है। आंध्र प्रदेश राज्य बनाम

क्षेत्र, चंडीगढ़. (टुली, जे.)

गोदावर्ति काशीविश्वनाधाम (5) में, आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के संदर्भ में यह देखा गया कि- * "पूरे अधिनियम में कर और जुर्माने के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास रखा गया है।

धारा 11, 14, 16, 17, 18, 21(4)(ए)(i) और (ii) और 30(एल)(ए) कर और जुर्माने का उपयोग एक साथ करते हैं और उन्हें अलग और अलग रखते हैं। कर लगाने में हमेशा जुर्माना लगाना शामिल नहीं होता है। वास्तव में, यह वह प्रावधान है जिसके तहत कर का आकलन और जुर्माना लगाया जाता है।

निर्णय के पृष्ठ 11 पर यह देखा गया है: -"अधिनियम के कई प्रावधानों में जुर्माना लगाने और वसूलने का भी स्पष्ट रूप से निपटारा किया गया है। ऐसा अवश्य ही होना चाहिए। इस प्रकृति के कर कानून में, विधानमंडल को उन मामलों की परिकल्पना और प्रावधान करना चाहिए, जहां करदाता अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने और इसके तहत लगाए गए उचित कर के भुगतान से बचने का प्रयास करते हैं। यदि ऐसी आकस्मिकताओं की कल्पना नहीं की जाती है और ऐसे लीक को बंद नहीं किया जाता है, तो कोई भी कराधान कानून प्रभावी ढंग से और संतोषजनक ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है। अपने प्रावधानों को संतोषजनक और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, आम तौर पर सभी कराधान कानूनों में दंड का प्रावधान किया जाता है। ऐसी मंजूरी के बिना कर चोरी का खतरा है। इस प्रकार, उनकी आवश्यकताओं का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने और वसूलने का प्रावधान, ऐसे अधिनियमों का एक अभिन्न अंग और उनके उद्देश्यों में से एक बन गया है। इस प्रकार यह तर्क कि यह अधिनियम के उद्देश्यों का हिस्सा नहीं है, पूरी तरह से अस्थिर है।

पृष्ठ 12 पर यह आगे देखा गया है-

"बिक्री कर अधिनियम के तहत निर्धारित या लगाया गया कोई भी कर और/या जुर्माना, मृतक डीलर द्वारा देय, मृत डीलर की संपत्ति से देय है। नियम 23(1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि उन्हें केवल मृत डीलर की संपत्ति से भुगतान किया जाना है। ऐसा प्रावधान हमें काफी उचित भी प्रतीत होता है। यदि मृत डीलर को कुछ अनियमितताओं के कारण कर और जुर्माना देना पड़ा, तो उसकी संपत्ति को ऐसी देनदारी से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि वह जीवित होता, तो वे उससे और उसकी संपत्ति से वसूल किये गये होते। संपत्ति को इस दायित्व से बचने की अनुमति देना अनुचित है, क्योंकि डीलर की मृत्यु हो गई थी। यदि कर उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति से वसूला जा सकता है, तो जुर्माना भी उसी तरह से वसूला जाना चाहिए।

(5) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि लगाया गया जुर्माना एक टन हो जाता है कर का निर्धारण किया गया है और कर के समान ही वसूली योग्य है।

क्षेत्र, चंडीगढ़. (टुली, जे.)

इसलिए, यह अनुमान लगाना उचित है कि विधायिका का इरादा था एक डीलर पर जुर्माना लगाने वाले सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्न को इस न्यायालय में संदर्भित करने की अनुमति दें। यदि ऐसे संदर्भ की अनुमति नहीं दी जाती है, तो कुछ मामलों में विषम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए कि किसी डीलर पर कर के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है और कर निर्धारण के मामले में बिक्री कर न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्न पर एक संदर्भ की अनुमति दी गई है और उस प्रश्न का निर्णय डीलर के पक्ष में किया गया है। डीलर और यह माना जाता है कि निर्धारित कर अवैध या अन्यायपूर्ण था। यदि जुर्माना लगाने वाले आदेश के खिलाफ कोई संदर्भ की अनुमति नहीं है और जुर्माना वसूल कर लिया गया है, तो ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके द्वारा डीलर सरकार द्वारा उससे अवैध रूप से वसूल की गई जुर्माना राशि वसूल कर सके। यह केवल इस न्यायालय को दिए गए एक संदर्भ पर होगा कि डीलर की जुर्माना अदा करने की गैर-देनदारी भी इस आधार पर तय की जाएगी कि निर्धारित कर कानूनी नहीं था और इसलिए गैर-भुगतान के कारण कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। उस कर का। इसलिए, हम मानते हैं कि पंजाब अधिनियम की धारा 22(1) में इस्तेमाल किए गए शब्द "कर" में कर निर्धारण और लगाया गया जुर्माना दोनों शामिल हैं और जुर्माना लगाने वाले बिक्री कर न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्न पर एक संदर्भ दिया जा सकता है। उस धारा के तहत इस न्यायालय में किया जाएगा।

(6) इसलिए, इस याचिका को अनुमति दी जाती है और बिक्री कर न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ को निर्देश दिया जाता है कि वह पंजाब अधिनियम की धारा 22(1) के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन पर गुण-दोष और यदि कोई प्रश्न या कानून का प्रश्न हो, के आधार पर निर्णय ले। यदि उसके आदेश से उत्पन्न होना पाया जाता है, तो उस प्रश्न या उन प्रश्नों को मामले का उचित विवरण तैयार करने के बाद इस न्यायालय को भेजा जा सकता है। चूंकि मामला कठिनाई से मुक्त नहीं था, इसलिए पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

बी.एस.जी.

अवीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए एहताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावहान्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मेसर्स चरणजीत लाल, देस राज बनाम सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल,

क्षेत्र, चंडीगढ़. (टुली, जे.)

वसुंधरा राव
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी,
हरियाणा